SHRI SANJAY SINGH (National Capital Territory of Delhi): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI B. LINGAIAH YADAV (Telangana): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री सभापतिः एसोसिएट करने वाले सदस्य स्लिप भेज दीजिए। श्री नीरज डांगी।

Demand to declare the Eastern Rajasthan Canal Project as National Project

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख के जरिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के समक्ष रख रहा हूं।

महोदय, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ इसका क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 10 प्रतिशत है, परन्तु राज्य में भू-जल की उपलब्धता मात्र 1.72 प्रतिशत ही है। प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना तैयार कर वर्ष 2017 में केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी। लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपए की इस परियोजना से मॉनसून के दौरान नदियों के अधिशेष जल का संरक्षण कर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है। स्वीकृत परियोजना में यह परियोजना सबसे बड़ी होने के बावजूद भी राजस्थान की इस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधान मंत्री जी के समक्ष यह मामला उठाया था। मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में प्रधान मंत्री जी को राजस्थान प्रवास के दौरान अजमेर की जनसभा में किया गया उनका वादा याद दिलाते हुए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

MATTERS RAISED WITH PERMISSION - *Contd.*

Need to enact a strict law to stop adulteration of milk

श्री सभापति: श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला । आपका ज़ीरो ऑवर वाला नोटिस है, उसके बारे में संक्षेप में बोल दीजिए।

श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला (गुजरात): सर, यह आज है? सर, मुझे कल के बारे में बताया गया था।

श्री सभापतिः हाँ, आज है।